

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1829/2013

पन्नालाल

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.07.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं दे रहा है। प्रकरण पुराना है। अतः अपील का निस्तारण पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के आधार पर किया जा रहा है।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर दिनांक 05.12.1988 को नियुक्ति प्रदान की। अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से लगातार अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर कार्यरत है। स्थापना समिति जिला परिषद श्रीगंगानगर की बैठक दिनांक 13.10.1999 में लिये गये प्रस्ताव के अनुशरण में जिले में कार्यरत अध्यापकों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवाएं नियमित करने के आदेश प्रदान किये। आदेश दिनांक 26.02.2006 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीगंगानगर ने आदेश पारित कर अपीलार्थी की सेवाएं प्रथम नियुक्ति तिथि 12.12.1988 से नियमित करने के आदेश जारी किये। जिला परिषद श्रीगंगानगर के अनुशरण में पंचायत समिति, रायसिंहनगर में अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 12.12.1997 से प्रदान किया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तिथि 12.12.1988 थी। अतः उसने सेवा में 18 वर्ष दिनांक 12.12.2006 को पूर्ण कर लिये थे, परंतु राज्य सरकार ने उसे द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 18.12.2010 से देने के आदेश जारी किये एवं अपीलार्थी को 9300—34800 ग्रेड—पे 3600 में फिक्स किया गया। उक्त आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 03.08.2012 के द्वारा

- अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ उसके 9 वर्ष पूरे करने की तिथि से प्रदान किये गये थे, परन्तु उसे द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ 18 वर्ष पूर्ण करने की तिथि से नहीं दिया गया है। अपीलार्थी ने अपनी 18 वर्षीय सेवा दिनांक 12.12.2006 को पूर्ण कर ली थी। अतः वह अपने 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी ने अपना 18 वर्षीय सेवाकाल दिनांक 12.12.2006 को पूर्ण कर लिया था। ऐसे में अपीलार्थी दिनांक 12.12.2006 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु बिना किसी कारण के अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 12.12.2006 से न दिया जाकर दिनांक 12.12.2010 से दिया गया है, जो गलत है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना की गयी है कि अपीलार्थी की सेवा की गणना दिनांक 12.12.1988 से करते हुए अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 12.12.2006 से दिये जाने का आदेश पारित करें।
 4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का चयन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आदेश दिनांक 12.12.1992 से किया गया पंचायतीराज में नियुक्त अध्यापकों को द्वितीय चयनित वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान 2008 नियमों के अनुसरण में चयनित वेतनमान स्क्रीनिंग तिथि से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 12.12.2010 से देय है, जो नियमानुसार लाभ दे दिया गया। स्क्रीनिंग के पश्चात पारित आदेशों के अनुसार ही सेवा सम्बन्धी समस्त लाभ परिलाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी होने से उक्त अपील मय कोस्ट के काबिल निरस्त योग्य है, जो निरस्त फरमायी जावे।
 5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
 6. अपीलार्थी ने अपनी प्रथम नियुक्ति का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु अपीलार्थी ने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी की सेवा बाद में नियमित की गयी है। अतः अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी रूप से हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गयी और अपीलार्थी को स्क्रीनिंग के बाद नियमित किया गया है।
 7. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की

पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

- "(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
- (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
- (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
- (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
- (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct

law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

8. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाएं स्क्रिनिंग के पश्चात ही नियमित की गयी है। उससे पूर्व की सेवा तदर्थ रूप में दी गयी थी। नियमितिकरण की दिनांक से ही अपीलार्थी की सेवाएं नियमित मानी जा सकती है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवाएं मानी जानी चाहिए। यह भी माना है कि वरिष्ठता एवं अन्य लाभों के सम्बन्ध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारीखे नहीं हो सकती। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं स्क्रिनिंग के बाद नियमित की गयी है, उससे पूर्व की सेवा को अपीलार्थी वरिष्ठता एवं अन्य लाभों के लिये अपनी सेवा में नहीं जुडवा सकता है।
9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)